

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY



ਸ਼ਂ. 186] No. 186] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 30, 2000/चैत्र 10, 1922 NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 30, 2000/CHAITRA 10, 1922

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2000

सा.का.नि. 271(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :— ''सं. आ. 176''

संविधान (राजस्व वितरण) संख्यांक आदेश, 2000

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 275 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वित्त आयोग की मिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात् :—

- 1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम संविधान (राजस्व वितरण) संख्यांक आदेश, 2000 है।
- 2. साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) इस आदेश के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह किसी केन्द्रीय अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है।
- 3. (1) अनुच्छेद 275 के खंड (1) के उपबंधों के अनुसार 1 अप्रैल, 1999 को प्रारंभ होने वाले वर्ष में, नीचे विनिर्दिष्ट राज्यों में से प्रत्येक को राजस्वों के सहायता अनुदान के रूप में उनके सामने विनिर्दिष्ट राशियां, जो राज्यों में प्राकृतिक विपत्ति के संबंध में राहत देने के लिए राज्य विपत्ति राहत निधियों हेतु केन्द्रीय सरकार के अभिदाय के रूप में हैं, भारत की संचित निधि पर भारित होंगी :—

क्र. मं.	राज्य	(रुपए लाखों में)
	(1)	(2)
1.	आन्ध्र प्रदेश	10769.00
2	अरुणाचल प्रदेश	610.00
3	असम	4337.00

	(1)	(2)
4.	बिहार	3378.75@
5	गोवा	93.00
6.	गुजरात	12105.00
7. ,	हरियाणा	2173.00
8.	हिमाचल प्रदेश	2337.00
9.	जम्मू~कश्मीर	1709.00
0.	कर्नाटक	3629.00
1.	केरल	4804.00
2.	मध्य प्रदेश	4429.00
3.	महाराष्ट्र	4435.50@
4.	मणिपुर	161.25 <i>@</i>
5	मेघालय	242.00
6.	मिजोरम	110.00
7.	नागालैंड	147.00
8.	उड़ीसा	4250.00
9.	पंजाब	4696.00
0.	राजस्थान	15525.00
1.	सिक्किम	306.00*
2.	तमिलनाडु	5147.00
3.	त्रिपुरा	390.00
4.	उत्तर प्रदेश	8137.50*
25.	पश्चिमी बंगाल	4450.00 :

[्]यः बिहार, महाराष्ट्र और मणिपुर की बाबत क्रमशः 1126.25 लाख रुपए, 1478.50 लाख रुपए और 53.75 <mark>लाख रुपए रकम की</mark> चौथी तिमाही किश्तें जो सी.आर.एफ. के गठन से संबंधित जानकारी और निधि में केन्द्रीय और रा<mark>ण्य अंश जमा करने के अभाव</mark> में नहीं दी गईं।

परन्तु यह कि ऊपर विनिर्दिष्ट राशियां राज्यों में प्राकृतिक विपत्तियों के संबंध में राहत देने के लिए उपायों पर 1 अप्रैल, 1999 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष में व्यय की जाएंगी :

परन्तु यह और कि यदि राहत उपायों पर वास्तविक व्यय, जैसा कि उस वर्ष के लेखाओं में प्रकट किया गया है, ऊपर विनिर्दिष्ट राशियों में कम है तो अतिशेष, राज्य के विपत्ति राहत निधि के भाग के रूप में राज्य सरकार को उपलब्ध बना रहेगा।

(2) 1 अप्रैल, 1999 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष में किसी राज्य को उप पैरा (1) के अधीन संदेय राशियों की कोई राशि संविधान (राजस्व वितरण) आदेश, 1999 के पैरा 3 के उपपैरा (1) के अनुसरण में वित्तीय वर्ष में उस राज्य को संदेय राशि या राशियों के अतिरिक्त होंगी।

के. आर. नारायणन,

राष्ट्रपति।

^{* 1998-99} के दौरान क्रमश: सिक्किम और उत्तर प्रदेश की बाबत 102.00 लाख रुपए और 2712.50 लाख रुपए रकम की अग्रिम दी गई पहली तिमाही किश्तें।

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th March, 2000

G.S.R. 271(E).—The following Order made by the President is published for general information:—

"C O. 176"

THE CONSTITUTION (DISTRIBUTION OF REVENUES) ORDER, 2000

In exercise of the powers conferred by article 275 of the Constitution, the President, after having considered the recommendations of the Finance Commission, hereby makes the following Order, namely —

- 1 This Order may be called the Constitution (Distribution of Revenues) Order, 2000.
- 2. The General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of a Central Act.
- 3. (1) In accordance with the provisions of clause (1) of article 275, there shall be charged on the Consolidated Fund of India, in the financial year commencing on the 1st day of April, 1999, as grants-in-aid of the revenues of each of the States specified below, the sums specified against it as representing the contribution of the Central Government towards State Calamity Relief Funds for affording relief in connection with natural calamities in the States.—

SI No	State	(Rupees in lakhs)
	(1)	(2)
1.	Andhra Pradesh	10769 00
2.	Arunachal Pradesh	610 00
3.	Assam	4337.00
4	Bihar	3378.75@
5	Goa	93.00
6	Gujarat	12105.00
7.	Haryana	2173.00
8	Himachal Pradesh	2337 00
9.	Jammu and Kashmir	1709 00
10	Karnataka	3629.00
11	Kerala	4804.00
12.	Madhya Pradesh	4429 00
13	Maharashtra	44 35.50@
14.	Manipur	161 25@
15.	Meghalaya	242.00
16	Mizoram	110.00
17	Nagaland	147.00
18.	Orissa	4250.00
19.	Punjab	4696.00
20.	Rajasthan	15525.00
21.	Sikkim	306.00*
22.	Tamil Nadu	5147.00`

	(1)	(2)
23	Tripura	390.00
24	Uttar Pradesh	8137.50*
25	West Bengal	4450.00:

a Fourth quarterly instalments amounting to Rs. 1126-25 lakhs, Rs. 1478-50 lakhs and Rs. 53.75 lakhs in respect of Bihar, Maharashtra and Manipur respectively have not been released for want of information relating to constitution of Calamity Relief Fund and crediting the Central and State share into the Fund.

Provided that the sums specified above shall be expended in the financial year commencing on the 1st day of April, 1999 on measures for affording relief in connection with natural calamities in the States:

Provided further that if the actual expenditure on relief measures as revealed in the accounts of that year, is lower than the sums specified above, the balance shall remain available to the State Government as part of the Calamity Relief Fund of the State

(2) Any sum or sums payable under sub-paragraph (1) to any State, in the financial year commencing on the 1st day of April. 1999 shall be in addition to the sum or sums payable to that State in the financial year in pursuance of sub-paragraph (1) of paragraph 3 of the Constitution (Distribution of Revenues) Order, 1999.

K. R. NARAYANAN,

President.

[F No. 19(1)/2000-LI] RAGHBIR SINGH, Secy.

⁴ First quarterly instalments amounting to Rs. 102 00 lakhs and Rs. 2712 50 lakhs in respect of Sikkim and Uttar Pradesh respectively released in advance during 1998-99